Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका का अध्ययन

सुरेन्द्र कुमार[1], योगेन्द्र कुमार कुशवाहा[2]
1. **शोधार्थी (वाणिज्य),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।
2. **शोधार्थी (अर्थशास्त्र),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** surendra531998@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21425410

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इन क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास के लिए सहकारिता एक प्रभावी संस्थागत माध्यम के रूप में उभरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसानों, कारीगरों और मजदूरों को संगठित करके उन्हें वित्तीय सहायता, उचित बाजार, और बिचौलियों से मुक्ति दिलाती है। सहकारिता सहकार से समृद्धि के मंत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए साख सहकारी समितियां सदस्यों को उचित ब्याज दर पर कृषि और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करती हैं। किसानों को समय पर और किफायती दरों पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में सहकारी संस्थाएं (जैसे पैक्स) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विपणन सहकारी समितियां किसानों की उपज को सीधे बाजारों में बेचकर बिचौलियों को खत्म करती हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पादन का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। सहकारिता द्वारा हथकरघा, खादी, और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों और कारीगरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। सहकारी संस्थाएँ न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, रोजगार सृजन और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शोध पत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

आलेख सूचना
प्राप्त: 23 सितंबर, 2025 **स्वीकृत:** 07 नवंबर, 2025 **प्रकाशित:** 31 दिसंबर, 2025
सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 14
मुख्य शब्द: ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, ग्रामीण रोजगार, सतत विकास, समितियां।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना में सहकारिता एक आधारभूत स्तंभ है, जो कृषि ऋण, विपणन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अवसंरचना विकास (भंडारण/परिवहन) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैक्स (पीएसीएस) जैसे सहकारी संगठन स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, किसानों को किफायती इनपुट (बीज, खाद) और उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण लाते हैं। ग्रामीण भारत देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना की रीढ़ है। स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किए गए, जिनमें सहकारिता आंदोलन को विशेष महत्व दिया गया। सहकारिता का मूल सिद्धांत पारस्परिक सहयोग, लोकतांत्रिक प्रबंधन और सामूहिक लाभ पर आधारित है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बनी हैं।

2. सहकारिता की अवधारणा : सहकारिता का आशय 'मिलजुल कर साथ–साथ कार्य करने' से है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग अपनी स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। इसके सदस्य समानता और आपसी सहयोग के आधार पर लोकतांत्रिक रूप से सामूहिक विकास (पारस्परिक हित) के लिए कार्य करते हैं। इस तरह सहकारिता एक प्रकार की व्यावसायिक संरचना को संदर्भित करता

है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। सहकारी संस्थाएँ लाभ से अधिक सेवा को प्राथमिकता देती हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें गहरी हैं, विशेष रूप से कृषि ऋण, विपणन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण बैंकिंग के क्षेत्र में।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना : ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और छोटे उद्योगों (हस्तशिल्प) पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का वर्चस्व है। हाल के वर्षों में, गैर–कृषि गतिविधियां (जैसे निर्माण, सेवाएं) तेजी से बढ़ रही हैं और अब ग्रामीण आय का लगभग दो–तिहाई हिस्सा गैर–कृषि क्षेत्र से आता है। इसके अलावा, यह प्रणाली ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन उपयोग और 70 प्रतिशत श्रम बल को रोजगार प्रदान करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
1. प्राथमिक क्षेत्र में कृषि (खेती), पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन शामिल हैं, जो ग्रामीण जीवन और आय का मुख्य आधार हैं। भारत में छोटे और सीमांत किसान कृषि आबादी का 86 प्रतिशत हिस्सा हैं।
2. गैर–कृषि क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए गैर–कृषि गतिविधियों का महत्व बढ़ रहा है। इसमें लघु उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण विनिर्माण और व्यापार शामिल हैं।
3. तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, ग्रामीण बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसी सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग, वन एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों पर आधारित है, जबकि इन सभी क्षेत्रों में सहकारिता ने संगठित ढाँचा प्रदान कर उत्पादकता और आय में वृद्धि की है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में कृषि संकट, छोटे किसानों के पास कम भूमि, मौसमी रोजगार और बुनियादी ढांचे (विद्युत, पानी, स्वास्थ्य) की कमी जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। इसलिए सहकारिता की भूमिका का विस्तार करना आवश्यक हो जाता है।

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका :
4.1 कृषि क्षेत्र में सहकारिता : कृषि सहकारी समितियाँ किसानों को बीज, उर्वरक, ऋण तथा विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होता है।
4.2 ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन : ग्रामीण सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ छोटे और सीमांत किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करती हैं। इससे साहूकारों के शोषण में कमी आई है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
4.3 रोजगार सृजन में सहकारिता : सहकारी संस्थाएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार सृजित करती हैं। डेयरी, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आजीविका के अवसर प्राप्त होते हैं।
4.4 महिला सशक्तिकरण में सहकारिता : महिला सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। इससे सामाजिक स्थिति में सुधार और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।
4.5 सतत एवं समावेशी विकास : सहकारिता संसाधनों के सामूहिक उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देती है। यह मॉडल पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास तीनों को एक साथ साधने में सहायक है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की प्रमुख उपलब्धियां : भारत में सहकारिता आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में किसानों को कम ब्याज पर ऋण, उर्वरकों और बीजों की उचित आपूर्ति, उत्पाद का बेहतर विपणन, दुग्ध उत्पादन (अमूल) में आत्मनिर्भरता, और बिचौलियों के शोषण से मुक्ति शामिल है, जो ष्सहकार से समृद्धिष् के लक्ष्य को बढ़ावा दे रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता ने संस्थागत साख की उपलब्धता को बढ़ाया है। सहकारी समितियों ने साहूकारों पर निर्भरता को कम किया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता कृषि विकास और आपूर्ति को बढ़ाया है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि यंत्र उचित दरों पर मिलते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता ने विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ाया है। फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सहकारी विपणन समितियां (जैसे नाफेड) किसानों की उपज का विपणन करती हैं। साथ ही, चीनी मिलें और दुग्ध समितियां प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता ने रोजगार सृजन को बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां, जैसे मत्स्य पालन, बुनाई और श्रम समितियां, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाना, शीत भंडारण की सुविधा और ग्रामीण विद्युतीकरण में सहकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। अमूल के नेतृत्व

में सहकारी डेयरी आंदोलन ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है, जिससे लाखों ग्रामीण महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया गया है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन उचित मूल्य पर मिलता है। इस तरह, सहकारी आंदोलन ने किसानों, लघु कारीगरों और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन की प्रमुख चुनौतियाँ : भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप, पेशेवर प्रबंधन की कमी, अपर्याप्त पूंजी और सदस्यों में जागरूकता के अभाव जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण ने सहकारिता की स्वायत्तता को कम कर दिया है, जिससे ऋण की धीमी उपलब्धता और प्रशासनिक अकुशलता के कारण यह आंदोलन अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया है।

सहकारी समितियों में अक्सर राजनेताओं का वर्चस्व होता है, जिससे वे अपनी स्वायत्तता खो देती हैं और सदस्यों के बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। सहकारी संस्थाओं में कुशल और पेशेवर प्रबंधकों की कमी है, जिसके कारण इन संस्थानों का संचालन और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अक्सर देखा गया है कि सहकारी समितियों के पास ऋण देने के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी होती है और वे सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा सरकारी निकायों द्वारा अत्यधिक निगरानी के कारण समितियां स्वायत्त रूप से काम नहीं कर पातीं हैं।

जागरूकता का अभाव भी सहकारिता के विस्तार में बाधक रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सहकारिता के नियमों, सिद्धांतों और सहकारिता के फायदों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप समितियों का लाभ अक्सर छोटे किसानों की तुलना में धनी और प्रभावशाली ग्रामीण लोगों को अधिक मिलता है। पुरानी तकनीकों के इस्तेमाल और तकनीकी पिछड़ापन के कारण इन समितियों की उत्पादन और विपणन दक्षता कम होती है। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप सहकारिता का जो असली उद्देश्य 'समानता और सामूहिक विकास' है, वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देती है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशन और सतत विकास के लक्ष्यों को भी साकार करती है। वर्तमान चुनौतियों के समाधान और आधुनिक तकनीकों के समावेशन से सहकारिता भविष्य में ग्रामीण भारत के विकास की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। हालांकि, डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहकारिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि सरकारी नीतियाँ और सामुदायिक भागीदारी एक साथ आगे बढ़ें, तो सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत विकास की मजबूत आधारशिला बन सकती है।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. अग्रवाल, ए. (2018)। भारत में ग्रामीण विकास और सहकारिता। अटलांटिक पब्लिशर्स नई दिल्ली।
2. शर्मा, आर. के. (2020)। सहकारी आंदोलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
3. सिंह, बी. पी. (2019)। ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका। भारतीय अर्थशास्त्र समीक्षा, 12(2), 45–58।
4. मिश्रा, एस. (2017)। ग्रामीण भारतः समस्याएँ और संभावनाएँ। वाराणसी चौखंबा प्रकाशन।
5. यादव, डी. के. (2021)। कृषि सहकारिता और किसानों की आय। कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, 18(1), 33–47।
6. भारत सरकार. (2022)। राष्ट्रीय सहकारिता नीति। नई दिल्लीरू सहकारिता मंत्रालय।
7. पांडेय, एम. (2018)। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका। समाज विज्ञान शोध, 10(3), 61–72।
8. वर्मा, के. एल. (2016)। ग्रामीण वित्त और सहकारी बैंकिंग। नई दिल्ली प्रभात प्रकाशन।
9. सिंह, एन. एवं कुमार, आर. (2020)। ग्रामीण रोजगार सृजन में सहकारिता। ग्रामीण अध्ययन जर्नल, 7(2), 89–101।
10. चौधरी, ए. (2019)। सतत विकास और सहकारी मॉडल। पर्यावरण एवं विकास, 5(1), 22–34।
11. भारत सरकार (2021)। आर्थिक सर्वेक्षण। नई दिल्ली वित्त मंत्रालय।
12. त्रिपाठी, एस. (2017)। सहकारिता : सिद्धांत और व्यवहार। इलाहाबाद लोकभारती प्रकाशन।
13. गुप्ता, पी. (2020)। ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहकारिता की भूमिका। भारतीय ग्रामीण विकास, 9(4), 55–68।
14. कुमार, ए. (2018)। ग्रामीण विकास में संस्थागत ढाँचे. समकालीन भारत, 6(2), 40–52।

*****

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, सुरेन्द्र एवं कुशवाहा, योगेन्द्र कुमार (2025)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता की भूमिका का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 52–54।